श्री उपसभापतिः कलराज जी, समाप्त कीजिए।

श्री कलराज मिश्रः महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उन स्थानों को मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, लोगों की निगाह में डालना चाहता हूं, ताकि उन स्थानों को ध्यान में रखकर वहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था करें। जो भी हिंदी भाषी मारे गए हैं, उनकी आजीविका का प्रबंध करें, पूरा मुआवज़ा दें और जगह-जगह जो असमिया लोग हैं, इनके मन में भी विश्वास पैदा करें कि उग्रवादी वहां आने न पाएगा, इसलिए असमिया–गैर असमिया का मामला यहां बिलकुल नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर प्रभावी ध्यान दे, एक बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली है। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Alleged Beating of Indians in Germany

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आंतरिक आक्रोश के साथ अपनी बात इस सदन में रख रही हूं। आज से दो दिन पहले जिस तरह जर्मनी में भारत के लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया, उस दृश्य को टी.वी. पर देखकर और समाचार-पत्रों में उस घटना के बारे में पढ़कर हर भारतवासी का खून खौल रहा है।

उपसभापति जी, भारत और जर्मनी के बहुत गहरे व्यापारिक संबंध हैं। जर्मनी की हर बड़ी कंपनी भारत में व्यापर कर रही है और भारत से भी लोग जर्मनी में पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए और व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आठ भारतीयों को घेरा गया और लगभग पचास जर्मनियों ने उन पर हमला किया, सामने खड़े लोग "Foreigners go out" का नारा लगाते रहे, जर्मनी का कोई नागरिक उन्हें बचाने के लिए नहीं आया, इस पूरी घटना से लगता है कि जर्मनी में नया नाजीवाद पनप रहा है। मैं दुख के साथ कहना चाहती हूं कि इतनी बड़ी घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वह अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं आई। रूटीन प्रतिक्रिया जरूर आई। हमारे Foreign Office ने उनके Foreign Office से बात की, जर्मनी की सरकार ने रूटीन में निंदा कर दी, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन के बीच में सरकार को कहना चाहती हूं कि यह घटना इतनी गंभीर थी कि हमें तुरंत जर्मनी के राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाना चाहिए था। बुलाकर उसे अपना displeasure नहीं, अपना protest convey करना चाहिए था। प्रधान मंत्री जी को फोन उठाकर जर्मन चांसलर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन यह सब नहीं हुआ, इसीलिए मैं इस बात को सदन के अंदर उठा रही हूं कि इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं और अपेक्षित प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आती, तो यहां रहने वाले देश के वासी तो चिंतित होते ही हैं, लेकिन वहां रहने वाले देश के वासियों को बहुत दुख और बहुत क्षोभ होता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं, संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, कि वे विदेश मंत्री को, मुझे लगता है कि सारा सदन मेरे साथ इसमें शामिल होगा, हमारी इन भावनाओं से अवगत कराएं। जर्मनी के राजदूत को बुलाकर सरकार को अपना protest convey करना चाहिए और प्रधान मंत्री को चांसलर से बात करनी चाहिए और जो भारत के लोग जर्मनी में रह रहे हैं, उनकी पूरी-पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त और उसकी चिंता भारत सरकार को करनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यः सर, हम अपने आपको इससे सम्बद्ध करते हैं।

Issue of Pricing of Gas

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय,

गैस प्राइसिंग के बारे में मैं आज आपके बीच में कुछ कहना चाहता हूं। रिलायंस ने प्रोडक्शन शेयरिंग कॉंट्रेक्ट पर कृष्णा गोदावरी ब्लॉक के साथ अप्रैल 2000 में हस्ताक्षर किए। मई 2000 में गैस निकली और फरवरी-मार्च 2004 में दस हजार करोड़ का बजट कम्पनी ने सरकार को दिया और नवम्बर 2004 में दस महीनों की तहकीकात के बाद सरकार ने इस राशि की स्वीकृत्ति दे दी। अगस्त 2006 में कम्पनी के इस प्रस्ताव को बढ़ाकर 22 हजार करोड़ का कर डाला गया और इसकी भी स्वीकृत्ति दे दी गयी। फिर तीन महीने के अंदर इसे बढ़ाकर 36 हजार करोड़ का कर डाला गया और वह भी गैस की प्रस्तावित प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाए बिना। पैट्रोलियम मंत्रालय ने अल्पावधि में दस हजार करोड़ से गैस की कीमत 36 हजार करोड़ तक पहुंचा दी। प्रधान मंत्री की Economic Advisory Council की प्रति मेरे पास है। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऑथेंटिकेट करके सदन को दे सकता हूं। सर मैं उससे उद्धृत करता हूं कि M/s RIL has twice revised the capex without a proportionate increase in projected revenues. Higher capex and/or lower rates of extraction of gas would also reduce the pre-tax investment multiple on the basis of which the profit petroleum is shared between the Government and RIL. यानी, सरकार को 36 हजार करोड़ का चूना और रिलायंस को सीधा लाभ। केबिनेट सेक्रेट्री की रिपोर्ट भी मेरे पास है, मैं इसे भी ऑथेंटिकेट करके दे सकता हूं। हिन्दुस्तान के केबिनेट सेक्रेटरी की रिपोर्ट के पेज नम्बर 32 पर डीजी, हाइड्रो कार्बन, पैट्रोलियम मिनिस्ट्री और रिलायंस इंडस्ट्री की मिली-जुली सांठ-गांठ पर के.जी.बेसिन की गैस पर अधिक मूल्य वृद्धि पर तल्ख टिप्पणियां हैं। मेरे संज्ञान में है कि सरकार ने Empowered Group of Ministers की समिति आदरणीय प्रणव मुखर्जी जी की अध्यक्षता में बनायी है। मेरा प्रतिवेदन है कि केबिनेट सेक्रेटरी की रिपोर्ट और माननीय प्रधान मंत्री जी की Economic Advisory Council की रिपोर्ट, जो इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश करती है एवं माननीय मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश, जो आपके कांग्रेस के ही मुख्य मंत्री हैं और जिन्होंने दर्जनों पत्र इस घोटाले को संज्ञान में लाते हुए लिखे हैं, उनका पूरा संज्ञान यह Empowered Group of Ministers अपने विश्लेषण में करे। मेरी यह भी मांग है कि केबिनेट सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर की Economic Advisory Counil की रिपोर्ट सदन में रखी जाए। यदि उपसभापति महोदय अनुमति दें तो मेरे पास यह रिपोर्ट है, मैं इसे ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हूं ताकि देश को तमाम घोटालों से बड़े इस महाघोटाले से बचाया जा सके। सर, पैट्रोलियम मंत्रालय, एक सरकारी उपक्रम एनटीपीसी से, जो ऊर्जा मंत्रालय का है, के विरुद्ध एक निजी कम्पनी के हित के लिए न्यायालय तक में लड़ रहा है। पैट्रोलियम मिनिस्ट्री अपने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, सरकार के केबिनेट सेक्रेटरी, प्रधान मंत्री के Economic Advisory Council, ऊर्जा मंत्रालय के एनपीटीसी के मुकाबले रिलायंस के हित में ज्यादा चिंतित है। गैस की अधिक कीमत से फर्टिलाइज़र की मूल्य वृद्धि से किसानों का नुकसान होगा और खाद की मूल्य वृद्धि सब्सिडी की बढ़त कराएगी। फिर सब्सिडी की बढ़त के घाटे की आपूर्ति जनता पर अधिक टैक्स से की जाएगी और रिलायंस को windfall profit इकनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर मिलेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि कृपया इस घोटाले की जांच सीबीआई और सीएजी से कराई जाए।

सर, मैं एक विशेष उल्लेख यह भी करना चाहता हूं कि हमारे सदन के एक सांसद बनवारी लाल कंछल को कल लखनऊ के अंदर पुलिस ने ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः वह अलग बात है।

श्री अमर सिंहः सर, मैं उल्लेख कर दूं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः यह ज़ीरो ऑवर में आएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): इसका नोटिस दिया गया है।

श्री उपसभापतिः आपने नोटिस भेजा है, ज़ीरो ऑवर में ...**(व्यवधान)**...

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**...

† **شری شاہد صدیقی : اس کی انکوائری ہونی چاہئیے ۔مداخلت۔**

श्री उपसभापतिः ज़ीरो ऑवर सबजेक्ट अलग है, यह सबजेक्ट अलग है। ...**(व्यवधान)**... आपने नोटिस दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is under consideration. Report has been called ...*(Interruptions)*...

श्री शाहिद सिद्दिकीः इसकी जांच करायी जाए। ...**(व्यवधान)**...

† **شری شاہد صدیقی : اس کی جانچ کرانی جائے ۔مداخلت۔**

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश): इतना बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार इस घोटाले की जांच करे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... श्री तपन कुमार सेन।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Thank you, Mr. Deputy Chairman. Sir, the issue of gas pricing is a serious one. It is our natural resource, and it should be used in the national interest, and not to ensure windfall profit of the contractors, exploiting that natural resource. But the thing is moving in that direction, and that is why, there is an anxiety. Sir, the Petroleum Ministry's Committee has gone on record in the matter of pricing mechanism, where they have said that in the absence of market determined price through transparent bidding process, where valuation has to be done by the Government, it may be done, based on most recent competitively determined price, duly Indexed to the present. Now, the debate and the dispute is that the most recent price is discovered through international competitive bidding and arranged by NTPC and the lowest quote was by the RIL-NIKKO combine at 2.34 dollar million btu. That is the recent price, and that price of 2004, if indexed to the present, cannot ensure an 85 per cent hike, which the same contracting company is demanding from the Government for the KG Basin gas. Sir, the 2004-07 price can in no way justify an 85 per cent hike. And unfortunately, the kind of media expression that is coming as the reactions of different Government Departments, the Committee of Secretaries. etcetera, etcetera, is that they are inclined to accept that, asking for the moon by the concerned contracting company to fix the price of KG Basin at 4.33 dollar/mm btu at the well head. If this is agreed, and it this natural resource is allowed to be exploited to ensure windfall gain... *(Time Bell)*... Please let me complete.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am just giving you the first bell so that you can complete.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: ....for some private contractor. This will totally frustrate the Planning Commission's decided perception of substituting it by a

†Transliteration in Urdu Script.

cleaner fuel to the major polluting sector, the power sector, the fertiliser sector, the transport sector and the domestic sector because just one dollar increase in its price will mean a 33 paise per unit increase in the cost of power. So, this has got a serious implication.

And the last point relates to the basis of making a claim for 4.33 dollars. What is the basis? The claimant is putting linking the international prices of crude for fixing the price of natural gas which is produced from our soil. *(Time Bell)* Crude we are importing to the tune of 80 per cent from outside. The gas we are producing. For fixing the price of gas when... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tapan Kumar Sen, please conclude. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Sir, this is a very serious matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is all right. But everybody has followed the rule. He should also follow the rule. ...*(Interruptions)*... He has no exception. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*... Please conclude.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Just one minute, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, we are.....*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everybody has followed the rule by taking three minutes. Why should he take more than that? ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: In the matter of gas, there is no justification of linking the price with the import of international crude and the manner .....*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me follow certain rules. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I want to make a point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should only associate. That is all right. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, doubling the production four times itself is a matter of ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Next is Mr. Ravula Chandra Sekar Reddy, ...*(Interruptions)*... No, no; you have concluded. ...*(Interruptions)*... Mr. Ravula Chandra Sekar Reddy.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, it is an important issue. Let us discuss it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; in Zero Hour you should learn to sum up in three minutes. ...*(Interruptions)*... Otherwise, you give notice under some other rule, and do not speak like this during the Zero Hour.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I am concluding. I demand a full-fledged discussion in the House. Thank you, Sir.

SHRI YASHWANT SINHA (JHARKHAND): Sir, the only point I would like to make here is that let the Government respond to that issue which has been raised in this House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister is not here. In Zero Hour, the Chair cannot compel the Government to respond.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I do not know why it has been accepted. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I cannot answer. That has been admitted by the hon. Chairman. ...*(Interruptions)*... Mr. Reddy.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, we will give a notice for having a separate discussion. ...*(Interruptions)*... The Minister is here. Let him respond. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chatterjee, please sit down. ...*(Interruptions)*... No, no; this is not right. ...*(Interruptions)*... This is not right. ...*(Interruptions)*... This is not right. ...*(Interruptions)*... This is not right. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Siddiqui, please sit down. We have to follow the rules. When you give a notice under Zero Hour, it is a well-laid rule and convention that only three minutes are given, and asking for a response during Zero Hour, I would like to remind, is not a right. We have removed it from the rules. There is no rule for Zero Hour issues. In the rules, there is no Zero Hour, but still by convention, we are allowing you to raise matters of urgent public importance to just mention them. But if you want to have the response of the Government immediateJy, why do you give a notice under Zero Hour? You should ask for a discussion under any other rule. ...*(Interruptions)*...

Please listen to me. ...*(Interruptions)*... Please listen to me. ...*(Interruptions)*... The Chair can't ask the Government to respond to Zero Hour submissions. ...*(Interruptions)*... It is for the Government to decide. ...*(Interruptions)*... If it wants to respond, let it respond. I have no objection. ...*(Interruptions)*... The Chair can't ask the Government, "You please respond". ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): We are demanding a discussion. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government is there. ...*(Interruptions)*... The Government is listening to you. ...*(Interruptions)*... Mr. Ravula Chandra Sekar Reddy. ...*(Interruptions)*...

Demand for Safe Return of Andhra Pradesh Labourers Stranded in the U.A.E. and other Gulf Countries and Providing them Employment

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I have been trying to raise this issue since 21st August. ...*(Interruptions)*... This is an urgent